भाकृअनुप—कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जी.टी. रोड, रावतपुर, कानपुर – 208 002 (उत्तर प्रदेश) An ISO 9001:2015 Certified



दि. 23-12-2020

कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम को

अंतिम रूप देने हेतु बैठक का आयोजन

दि. 22 दिसम्बर 2020 को भाकृअनुप एवं मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार के सहयोग से कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा मत्स्यपालन का प्रशिक्षण देने हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिये बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 600 से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों के अध्यक्ष एवं मत्स्य एवं पश् विज्ञान के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इसकी जानकारी डा. अतर सिंह, निदेशक, भाकृअनुप–अटारी कानपुर ने दी।

डा. त्रिलोचन महापात्रा, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकृअनुप ने कहा कि हमारा उद्देश्य मत्स्यपालन के क्षेत्र में मत्स्य पालकों की आय बढ़ाना है। इस दिशा में हमारे अनुभवों को तेजी से किसानों तक अधिक गति प्रदान करें। अतिरिक्त धनराशि कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रदान की जा रही है। एक लाख किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है। नये कृषि मोबाइल एप द्वारा 70 लाख कृषक तक प्रयोग करके कृषि विज्ञान केन्द्रों व अन्य विभागों से जुड़े हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को मत्स्यपालन के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए आनलाइन माध्यम का प्रयाग करें। केवीके को नियमित रूप से रिपोर्टिंग करनी है तथा सभी तक पहुँचना चाहिए। मत्स्यपालकों तक पहुँचकर हैचारी, और गुणवत्तायुक्ता युक्त खाद्य पदार्थ हेतु नेटवर्क करके पहुँचना है। 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के लिये। केवीके के माध्यम से तकनीकी विडियो व पाठ्य सामग्री वैल्यूएडीशन, मत्स्यबीज उत्पादन आदि पर साहित्य उपलब्ध कराये जायें। मूल्य शंखला, व्यवसाइयों तक पहुँचें। प्रत्येक जिले में 100 व्यवसायी प्रशिक्षित किये जायें। डा. राजीव रंजन, सचिव मत्स्यपालन विभाग ने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है। 1.24 प्रतिशत मत्स्य का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में है जबकि कृषि का 7.25 प्रतिशत योगदान है। सी फूड में भारत अग्रणी है। कृषि विज्ञान केन्द्रों को मास्टर ट्रेनर हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे वे किसानों को प्रशिक्षित कर सकें। आय सम्वर्धन का 1 लाख करोड़ का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्यपालन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करके नीली क्रांति लायी जा रही है तथा भारत 9 बिलियन यू.एस. डालर का उत्पादन कर रहा है। अभी तक गैर सरकारी संस्थानों का योगदान है। किसानों को मत्स्यपालन हेतु नये क्षेत्रों की पहचान और चारे उत्पादन में तेजी से पहुँचाया जाये। अभी फ्रेश वाटर मत्स्य पालन के साथ ही पेगाशियम तथा कैज उत्पादन के साथ ही खारे पानी में मत्स्य उत्पादन की जानकारी पहुँचायी जाये।

डा. जे.के. जेना, उपमहानिदेशक (मत्स्यपालन) ने कहा कि 5 प्रतिशत से पैदावार को 7 प्रतिशत बढ़ाया जाये। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रू 2000 करोड़ का धन उपलब्ध कराया है। भारत सरकार का अगले 5 वर्षों में 8 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य है। योजना के माध्यम से देश में मत्स्य पालन का तेजी से विकास हा। मछलियों के चारे पर शोध, नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने के अवसर है। संदेशों को क्षेत्रीय भाषा में ग्रामीणों तक पहुँचाने में कृषि विज्ञान केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 500 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 10 लाख किसानों तक तकनीक का प्रचार प्रसार किया जायेगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड आनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन करेगा जिसे मत्स्य व पशुपालन के वैज्ञानिक और कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से आगे की रिपोर्टिंग की जाये।

इस अवसर पर डा. राजीव रंजन, सचिव मत्स्यपालन विभाग, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकृअनुप डा. त्रिलोचन महापात्रा, डा. जे.के. जेना उपमहानिदेशक (मत्स्य), डा. ए.के. सिंह उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार), सहायक महानिदेशकगण, अटारी कानपुर निदेशक डा. अतर सिंह एवं समस्त अटारी निदेशक व कृषि विज्ञान केन्द्रों के अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक उपस्थित रहे।



ICAR-AGRICULTURAL TECHNOLOGY APPLICATION RESEARCH INSTITUTE

G.T. Road, Rawatpur, (Near Vikas Bhawan) Kanpur – 208 002

(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION)

Dated: 23.12.2020

Organizing a meeting to finalize the program of training for fisheries through Krishi Vigyan Kendras

On 22 December 2020, a meeting was organized to finalize the proposed training program for training of SMS Fisheries and Animal science by KVKs in collaboration with ICAR and National Fisheries Development Board in which the Heads of more than 600 Krishi Vigyan Kendra and related SMSs took part; Dr. Atar Singh, Director, ICAR-ATARI, Kanpur gave this information.

Dr. Trilochan Mohapatra, Secretary DARE and Director General ICAR said that our objective is to increase the income of fishermen in the field of fisheries. In this direction, let our experiences speed up the farmers faster. Additional funds are being provided to Krishi Vigyan Kendras. One lakh farmers can be benefitted. Through the new Krishi mobile app, up to 70 lakh farmers have been associated with Krishi Vigyan Kendras and other departments and are getting benefits. Our main objective is to increase production and productivity in the fisheries sector. Information about fisheries should be provided to farmers through Krishi Vigyan Kendras. For this, use online medium. KVK has to report regularly and reach out to all. Reaching the fisheries by networking them for hapless, and quality foods, for the Prime Minister's program on 25 December. Through KVK, technical videos and textual content, literature on fish seed production etc. should be made available. Reach the value chain, businessmen. 100 entrepreneur should be trained in each district.

Dr. Rajiv Ranjan, Secretary Fisheries Department said that India is the second largest fishery producer in the world. 1.24% of fishery contributes to the gross domestic product while agriculture contributes 7.25%. India is a leader in sea food. Krishi Vigyan Kendras will be trained creating master trainers so that they can further train the farmers. There is a target of 1 lakh crores of income augmentation. Through the Prime Minister Matsya Sampada Yojana, blue revolution is being brought in the field of fisheries by strengthening the infrastructure and India is producing 9 billion US dollars. Yet non-governmental institutions contribute in Identification of new areas for fisheries and fodder production. Now, along with fresh water fisheries, information about fish production in salt water should be communicated along with pegasium and cage production.

Dr. J.K. Jena, Deputy Director General (Fisheries) said that the yield should be increased from 5% to 7%. In the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, funds of Rs 2000 crore have been provided. The Government of India has a target of producing 8 million tonnes in the next 5 years. There should be rapid development of fisheries in the country through the scheme. There is a need to work on fish bait research, adoption of new techniques. There are opportunities to increase quality and production in collaboration with agricultural science centers. Krishi Vigyan Kendras have an important role in communicating the message to the villagers in the regional language. Technology will be disseminated to 10 lakh farmers through 500 Krishi Vigyan Kendras. The National Fisheries Development Board will conduct online training which will be further reported through the fisheries and animal husbandry scientists and agricultural scientists.

On this occasion, Dr. Rajiv Ranjan, Secretary Fisheries Department, Dr. Trilochan Mohapatra Secretary DARE and Director General ICAR, Dr. J.K. Jena DDG (Fisheries), Dr. A.K. Singh DDG (Agricultural Extension), ADGs, Dr. Atar Singh Director ATARI Kanpur and all ATARI Directors and heads of KVKs were present.







